दैनिक जागरण

चरित्र सबसे बड़ा धन है जिसकी सावधानी से रक्षा की जानी चाहिए

जोखिम भरे रास्ते

यह गंभीर चिंता का विषय बनना चाहिए कि देश की राजधानी से सटे ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ने वाला यमुना एक्सप्रेस वे एक और भीषण हादसे का गवाह बना। इस बार उत्तर प्रदेश रोडवेज की एक बस बेकाबू होकर गहरे नाले में जा गिरी। इस हादसे में करीब तीस यात्रियों की जान चली गई। इस हादसे पर प्रधानमंत्री समेत अन्य अनेक प्रमुख लोगों ने शोक व्यक्त किया है, लेकिन क्या इन शोक संवेदनाओं से हालात बदलेंगे और जानलेवा सड़क हादसे थमेंगे? यह प्रश्न इसलिए, क्योंकि मार्ग दुर्घटनाओं और उनमें मरने एवं घायल होने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि चंद दिनों पहले जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में एक मिनी बस के खाई में गिरने से 35 लोग काल के गाल में समा गए थे। इसके थोड़े दिन पहले हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में एक बस के नाले में गिर जाने से 44 लोगों की मौत हो गई थी। करीब एक पखवाड़े के अंदर देश के विभिन्न हिस्सों में एक के बाद एक बस दुर्घटनाओं में सौ से अधिक लोगों की मौत यही बताती है कि अपने देश के रास्ते कितने अधिक जोखिम भरे हो गए हैं। किश्तवाड़ और कुल्लू के मामले में यह सामने आया था कि दुर्घटना का शिकार हुई बसों में क्षमता से अधिक यात्री सवार थे। यमुना एक्सप्रेस वे पर हुए हादसे का कारण बस ड्राइवर को झपकी आना और साथ ही बस की रफ्तार कहीं तेज होना बताया जा रहा है। तेज रफ्तार वाहनों और लापरवाही के कारण यमुना एक्सप्रेस वे लगातार गंभीर दुर्घटनाओं से दो-चार हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह मान लिया गया है कि एक्सप्रेस वे पर तो दुर्घटनाएं होना लाजमी ही है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर मार्ग दुर्घटनाओं को रोकने के उपाय क्यों नहीं किए जा रहे हैं?

यह ठीक नहीं कि देश में जैसे-जैसे एक्सप्रेस वे तैयार होते जा रहे हैं वैसे-वैसे उनमें दुर्घटनाओं का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। निःसंदेह बेहतर सड़कें समय की मांग हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वे भीषण दुर्घटनाओं का गवाह बनती रहें। जिस तरह विभिन्न एक्सप्रेस वे पर दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं उसी तरह देश के पर्वतीय इलाकों के रास्ते भी। आम तौर पर हर बड़े सड़क हादसे के बाद उन्हें रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा होती है, लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ पहले की ही तरह होता हुआ दिखाई देता है। यही कारण है कि वर्ष दर वर्ष मार्ग दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तो यह संख्या सालाना डेढ़ लाख मौतों के आंकड़े को पार करने वाली है। मार्ग दुर्घटनाओं में मरने अथवा अपंग होने वाले लोगों की बढ़ती संख्या केवल संबंधित परिवारों के लिए ही आफत नहीं बनती, बल्कि वह समाज और देश को भी कमजोर करने का काम करती है, क्योंकि सड़क हादसों में मरने वाले ज्यादातर लोग अपने घर-परिवार के कमाऊ सदस्य होते हैं। बेहतर हो कि हमारे नीति-नियंता यह समझें कि जानलेवा सड़क हादसे रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने की सख्त जरूरत है।

भ्रष्ट व्यवस्था पर चोट

जम्मू-कश्मीर में भाजपा-पीडीपी गठबंधन सरकार के कार्यकाल में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में पिछले दरवाजे से हुई 101 नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से रद किए जाने का राज्यपाल प्रशासन का फैसला सराहनीय है। इसमें दो राय नहीं कि राज्यपाल जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के दौर में पैर पसार चुकी भ्रष्ट व्यवस्था पर चोट कर रहे हैं। राज्यपाल ने इससे पहले नेताओं और नौकरशाहों पर यह कहते हुए निशाना साधा था कि विकास के लिए आए धन से उन्होंने अपने घर तो भरे, लेकिन समाज की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया। जम्मू-कश्मीर में भ्रष्टाचार सबसे ज्वलंत मुद्दा है। बेशक पिछले कुछ दिनों में जिस तरह भ्रष्ट अधिकारियों के ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं, उससे राज्यपाल प्रशासन की गंभीरता नजर आती है। विडंबना यह है कि जैकफेड के जिन अधिकारियों के ठिकानों पर छापे मारे गए, उनमें से तो कई सेवानिवृत्त हो गए थे। सेवानिवृत्त अधिकारियों ने अकूत संपत्ति अर्जित की। यह एक दो माह पहले की नहीं, बल्कि कई वर्षों की दो नंबर की कमाई है। विडंबना यह है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कई योजनाएं बनीं। यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के मुद्दे को घोषणा पत्र में भी शामिल किया। इतना ही नहीं सरकार बनने पर मुफ्ती मुहम्मद ने भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए कई कदम उठाते हुए करीब साढ़े चार सौ अधिकारियों की सूची तैयार की। पूर्ववर्ती सरकार ने करीब सौ से अधिक भ्रष्ट अधिकारियों को बाहर का रास्ता तो दिखा दिया, लेकिन स्टेट विजिलेंस ने अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट में पेश किए गए चालान को इतना कमजोर बना दिया कि अधिकतर आरोपी नौकरी में बहाल हो गए। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो अभी भी स्वायत्त नहीं है। ब्यूरो अभी भी राज्य गृह विभाग के अधीन है। जब तक विजिलेंस ब्यूरो को पूर्ण स्वायत्तता नहीं मिलेगी तब तक राज्य में भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लग सकती। ब्यूरो विभागों के भ्रष्ट नौकरशाहों पर नकेल कसने में कतराता है। उन्हें डर रहता है कि अगर अपने से बड़े अधिकारी पर शिकंजा कसा गया तो वे उन्हें छोड़ेंगा नहीं। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को स्वायत्तता दी जाए, जिससे कि वह निर्भीक होकर अपना काम करे।

सुखद भविष्य का संकेत देने वाले प्रसंग

गोपालकृष्ण गांधी

कुछ मसलों पर प्रधानमंत्री के विचार और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के इस्तीफे का निर्णय बेहतर भविष्य की आस जगाता है

पिछले कुछ सप्ताहों की चार घटनाओं से मुझे बहुत संतोष हुआ, बल्कि यह कहें कि आनंद मिला। संतोष और आनंद में कोई अंतर है? नहीं भी है और है भी। पर्याय से हम परिचित हैं। फिर प्रश्न उठता है कि एक ही भाषा में एक ही अर्थ के दो-दो भिन्न शब्द क्यों? ठीक सवाल है और सवाल में ही उसका जवाब है। पर्याय से हमें दो शब्द नहीं, लेकिन एक सूक्ष्म विकल्प मिलता है, जिसकी भाषा और विचार को जरूरत है। पूरक की सहायता से पर्याय का अंतर साफ होता है। संतोष फुल्का है, आनंद पूड़ी। संतोष रसगुल्ला है, आनंद रसमलाई। संतोष सौंफ है, सुपारी भी, लेकिन आनंद है स्वादों से भरा बनारसी पान। आह! तो ये चार प्रसंग कुछ ऐसे हैं:

पहला: अभी हुए हमारे निर्णायक आम चुनावों में भोपाल निर्वाचन क्षेत्र के आंदोलन-प्रचार ने हमें एक दुखभरा अनुभव दिया। मैं उसकी अंतर्वस्तु में नहीं जाना चाहता। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने गांधी-गोडसे को लेकर जो कहा सो कहा। क्या कहा, हम सब जानते हैं, लेकिन आनंद! हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यथाशीघ्र उस बयान का खंडन किया। साध्वी ने एक वार्ता में कहा-मैं देशवासियों से माफी मांगती हूं...। क्षमा-प्रार्थना जो है, वह वार्तालाप की दुनिया से ऊपर, साहित्य से भी कुछ आगे, काव्य के क्षेत्र में संचार करती है। मेरा अर्थ सरसरी या मजबूरन मांगी हुई क्षमा से नहीं। मेरा अर्थ हृदय से क्षमा-याचना से है और मैं मानना चाहूंगा कि साधु-साध्वी जो कहते हैं वह सच होता है। अगर गेरुआधारी कोई झूठ बात कहता है तो वह साधु नहीं, अभिनेता है। मैं मानना चाहूंगा कि साध्वी प्रज्ञा ने जब देश की जनता से अपने कहे पर क्षमा मांगी तो वह अपने साधु-दिल से मांगी, न कि किसी सियासी-दिमाग से। मुझे उन दिनों पूछा गया, टिप्पणी दीजिए! कुछ सोचकर मैंने कहा कि गांधीजी अगर होते तो कहते, साध्वी को भगवान क्षमा करे। क्षमा मांगना बहादुरी का परिचायक है। क्षमा करना बड़प्पन का और जब वह (मांगने और देने की) क्रिया पूर्ण होती है तो नैतिकता को आनंद होता है, मानवता को आनंद होता है, शिष्टता को, शिष्टाचार को, सभ्यता को, संस्कृति को आनंद होता है। मुझ अदना-इंसान को भी आनंद हुआ। यहां यह कहना जरूरी है (सच्चाई के तौर पर) कि उस चुनाव में मेरी प्रार्थनामय मंशा थी कि गरीब-नवाज, पिछड़ों के दोस्त, समता-सेवक दिग्विजय सिंह विजयी होएं, देश के नेतृत्व में अपनी अनमोल भूमिका निभाएं। वह बात अलहदा है। जीवन में हम सब न जाने कितने विरोधाभासों को लेते हुए चलते हैं। यह आनंद-दर्द-आनंद का मिश्रण जीवन में मेरी एक दुविधा है। बहरहाल दर्द खुशी का बड़ा भाई है। वह बहना को इन्कार नहीं करता।

दूसरा: विजय-प्राप्ति के बाद अपनी पहली मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने राजनीति, चुनाव, सियासी हार-जीत को परे रखते हुए ऐसी बात उठाई जो हमारे लिए महत्व क्या, जिंदगी-मौत का सवाल है- पानी की किल्लत। उत्तर भारतीयोंके लिए कल्पना करना मुश्किल है कि चेन्नई में

अवधेश राजपूत

(जहां मैं रहता हूं) और देश के कई हिस्सों में बारिश के विलंब से अकाल चल रहा है। भूख से भी इंसान कुछ समय निपट सकता है। प्यास की बात अलग होती है और प्यास सिर्फ पीने के पानी की नहीं है। खेती प्यासी है, उद्योग प्यासा है। अस्पतालों, स्कूलों और छात्रावासों के नलके सूखे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि हमें बूंद-बूंद की किफायत करनी है तो मैं आनंदमय हो गया। पानी के बारे में पर्यावरणविद् बोलते हैं, पॉलिटिशियन-लोग नहीं, क्यों? क्योंकि यह विषय, यह चेतावनी, यह हिदायत लोकप्रिय नहीं। पानी कम हो गया है, यह एक गंभीर संदेश है। पानी का ध्यान से इस्तेमाल करें, यह एक कठिन सलाह है। उससे कोई वोट नहीं मिलने वाले, उससे कोई वाहवाही नहीं मिलने वाली, लेकिन प्रधानमंत्री का फर्ज बनता है कि कड़वे सच बोलें। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में वह कड़वा सच बोला। मैं प्रभावित हूं, आनंदित हूं। क्या इस संदेश को देश के उद्योगपति और शहरी अमीर सुनेंगे? आवश्यक है कि वे इसे औरों से पहले और उनसे ज्यादा ध्यान से सुनें, क्योंकि उद्योगपति और शहरी अमीर ही पानी का सबसे भारी उपयोग करते हैं। अगर ये सब प्रधानमंत्री के आह्वान को सुनें तो क्या बात होगी। वे जरा सोचें, समझें और अपने मुनाफे में कुछ नियंत्रण बरतें।

तीसरा: मैं आकाश विजयवर्गीय-कांड के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। बहुतों ने बहुत कुछ कह दिया है। मैं सिर्फ प्रधानमंत्री जी के बयान के बारे में इतना कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो कहा है, वह सराहनीय ही नहीं, अनुकरणीय है। राजनीति में संयम बोली में, आचार में जरूरी है। वह नहीं तो राज कहां, नीति कहां? और अगर संयम, आत्म-संयम, आत्म-नियंत्रण, आत्म-अनुशासन का उदाहरण हमारे राजनेता नहीं देते हैं तो हमारा राजनीतिक भविष्य समझिए खत्म। इतना ही नहीं, हमारी संस्कृति खतरे में होगी। अफसोस इधर के कई सालों से हमारे नेतागण यह नहीं देते आए हैं। उदाहरण कम नहीं, उदाहरण किसी एक दल या विचारधारा में सीमित नहीं, जो कि बतलाएंगे कि राजनीतिक बयानों और बर्ताव का स्तर कितना गिर चुका है। गत चुनाव में बहुत कुछ सुनने को आया, जिससे कान लाल हो जाते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आकाश विजयवर्गीय कांड के प्रसंग में जो सलाह दी है उसको पढ़-सुनकर दिल आनंदित हो गया। उन्हें धन्यवाद देता हूं, किंतु...क्या सियासी लोगों के साथ समाज को भी इस हिदायत की जरूरत नहीं? लिंचिंग शब्द अंग्रेजी का है, अमेरिका से आया हुआ, लेकिन उसका अर्थ आज हम सब जानते हैं। आकाश को दिया हुआ अत्यावश्यक सबक उन उन्मादियों को भी मिलना चाहिए, जो नफरत से उन पर वार करते हैं, जिनकी पहचान से उनको घृणा है। सच्चे पाठ की पूर्ति तभी होती है जब सारे दोषी उसके सहपाठी बनते हैं।

चौथा: पद-त्याग हमेशा एक ऊंची बात मानी गई है। उसमें नैतिकता निहित है, नेकी सम्मिलित है। कांग्रेस अध्यक्षता से मुक्त होना बिल्कुल जरूरी था राहुल गांधी के लिए। जवाबदेही करके भी कुछ होता है, यह हमारी राज-प्रणाली में लाल बहादुर शास्त्री ने सबसे पहले हमें दिखाया, जब वह रेल मंत्री थे। तमिलनाडु के अरियालुरु में रेल दुर्घटना के बाद उन्होंने एक क्षण भी सोचे बिना इस्तीफा दे दिया। माफी और इस्तीफा बहन-भाई हैं। राहुल गांधी ने अपने निर्णय पर डटे रहकर एक उत्तम उदाहरण दिया है। मैं आनंदित हूं, आभारी हूं। चुनाव में कांग्रेस की व्यापक पराजय का जिम्मा कांग्रेस के प्रादेशिक नेताओं से मांगना तब ही हो सकता है जब कांग्रेस अध्यक्ष स्वयं वैसा ही करें, लेकिन यह त्याग अपने लक्ष्य पर तभी पहुंचेगा जब अगला कांग्रेस अध्यक्ष एक ऐसा इंसान हो जो अपने बलबूते पर खड़ा या खड़ी हो, जो नेहरू-गांधी परिवार के इशारों पर न निर्भर हो, जो हार और दुर्भाग्य की कोख से महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आजाद की कांग्रेस को पुनर्जन्म दे और जो बाबासाहेब आंबेडकर, राजाजी, पेरियार, नेताजी, शहीद भगत सिंह, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और डॉ. लोहिया जैसे गैर कांग्रेसी नेताओं से ऊर्जा पाए। तभी राहुल गांधी का त्याग कांग्रेस और देश का सौभाग्य बनेगा।

(वर्तमान में अध्यापनरत लेखक पूर्व राजनयिक एवं पूर्व राज्यपाल हैं)

response@jagran.com

धर्म की महत्ता से अनजान वामपंथी

केसी त्यागी

वामपंथी यह समझें तो बेहतर कि वे भारतीय समाज में धर्म की व्यापक स्वीकृति को समझने में गलती कर गए

हालिया आम चुनाव में बंगाल में वाम मोर्चे को एक सीट भी नहीं मिली। एक प्रत्याशी को छोड़ सभी की जमानत जब्त हो गई। 27 वर्ष तक ज्योति बसु जैसे लोकप्रिय नेता के शासन के बाद वाम मोर्चे की ऐसी दुर्गति पर विश्लेषण आवश्यक हो जाता है। मार्क्सवादियों की धर्मनिरपेक्षता और धर्म से दूरी, दोनों ही विवाद के विषय बन गए हैं। एक जमाना था जब वामपंथी बंगाल के प्रमुख धार्मिक आयोजनों में शामिल होने में भी शर्म महसूस करते थे। कमोबेश यही स्थिति केरल में हुई जहां हाल के लोकसभा चुनावों में वाम मोर्चा एक को छोड़कर सभी सीटों पर पराजित रहा। इसका कारण सबरीमाला का विवाद बना। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के तहत इस मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति मिली, लेकिन सदियों पुरानी परंपरा उक्त मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को वर्जित करती है। मार्क्सवादी भारतीय समाज में धर्म की महत्ता समझने में गलती कर गए। वहीं भाजपा ने इसके विरुद्ध जन अभियान चलाया। इससे उसे लोकसभा की सीट तो नहीं मिली, लेकिन मत प्रतिशत में बढ़ोतरी जरूर आंकी गई। इस मसले पर प्रारंभ में काग्रेस पार्टी दुविधा में रही। चूंकि राज्य में भाजपा का संगठनात्मक ढांचा व्यापक नहीं था, इसलिए कांग्रेस वाले नेतृत्व को ही अप्रत्याशित जीत मिली।

हालांकि सबरीमाला घटनाक्रम से चिंतित होकर केरल के मार्क्सवादी संगठनों द्वारा कुछ प्रयास किए जा चुके हैं। केरल में सत्ताधारी माकपा के सांस्कृतिक संगठनों द्वारा 'रामायण महीने' का आयोजन किया जाना ऐसा ही प्रयास था। पिछले वर्ष जुलाई से अगस्त तक वहां मलयालम महीना कारकीडकम मनाने की परंपरा के साथ ही 'रामायण महीने'का आयोजन पार्टी का एजेंडा बना। वहां ऐसी मान्यता है कि इससे गरीबी एवं भीषण बारिश से होने वाली बीमारियों से मुक्ति मिलती है। इस दौरान राज्य के सभी 14 जिलों में संस्कृत संगम संस्था के सदस्यों द्वारा रामायण आधारित व्याख्यानमाला आयोजित की गई। केरल सरकार की इस पहल के बाद दलगत प्रतिक्रियाओं के तहत माकपा पर छवि बदलने की कोशिश जैसे आरोप भी लगे। ऐसी प्रतिक्रियाओं पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम्युनिस्टों एवं समाजवादियों की पहचान नास्तिक के रूप में रही है। धर्म को लेकर भारतीय समाज से इनकी दूरी बनी रही है। बंगाल में भी मार्क्सवादियों द्वारा दुर्गा पूजा के कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखना उन्हें भारी पड़ा। मार्क्सवादी चिंतन के लोग सभी तरह के धर्मों को क्रांति की राह में बड़ा रोड़ा मानते रहे हैं। लेनिन ने तो धर्म को अफीम तक कह दिया था। कम्युनिस्टों की पहचान ईश्वर और धर्म को नहीं मानने वाले के रूप में बन गई। समय के साथ यह धारणा विश्वव्यापी हो गई और धर्म

और कम्युनिस्टों के बीच दूरी बढ़ती चली गई। भारत के कम्युनिस्टों के वक्तव्य, आचरण एवं घोषणापत्र भी धर्म विरोधी होते गए। यद्यपि 1947 के बाद देश में कम्युनिस्टों का प्रभाव तेजी से बढ़ा। बंटवारे के बाद भी धार्मिक असहिष्णुता इतनी तीव्र नहीं थी जितनी आज है। कम्युनिस्टों के नेतृत्व में तेलंगाना का सशस्त्र विद्रोह और 1957 में नंबूदरीपाद के नेतृत्व में केरल में कम्युनिस्टों की पहली सरकार बनी। वहां के चर्च से जुड़े शिक्षण संस्थान भी कम्युनिस्टों के निशाने पर आ गए।

कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से अलग होकर डॉ. राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और नरेंद्र देव ने अलग दल का निर्माण किया। समाजवादियों में आचार्य नरेंद्र देव नास्तिक थे। जयप्रकाश भी धार्मिक आचरण से दूरी बनाए रखते थे। सबसे अनूठा और निराला व्यक्तित्व डॉ. लोहिया का रहा जिन्होंने राम, कृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर विस्तार से प्रकाश डालने का काम कर तुलनात्मक विश्लेषण भी किया। 1960 के दशक में उन्होंने अपने समाजवादी मित्रों एवं कार्यकर्ताओं को रामायण मेला आयोजित करने का सुझाव भी दिया। रामायण मेले से जुड़ा उनका यह वक्तव्य आज भी प्रासंगिक है कि 'धर्म और राजनीति का रिश्ता बिगड़ गया है। धर्म दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति अल्पकालीन धर्म। हम आज एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में हैं जिसमें बुराई से लड़ाई में धर्म का कोई रास्ता नहीं रह गया है और वह निर्जीव हो गया है, जबकि राजनीति अत्यधिक कलह भरी हो गई है।' मेले के आयोजन से उनका तात्पर्य पूछे जाने पर उनका उत्तर था, 'आनंद, दृष्टि, रस-संचार और हिंदुस्तान को बढ़ावा' इसके मुख्य उद्देश्य हैं। डॉ. लोहिया का स्पष्ट मत था कि धर्म और राजनीति की जड़ें एक हैं, लेकिन उनके दायरे को अलग-अलग रखना ही कल्याणकारी होगा। डॉ. लोहिया के अकस्मात निधन के बाद समाजवादी आयोजन दिशाहीनता का शिकार हो गया। मंडल के बाद की दलीय राजनीति ने इसे संकीर्ण और सिद्धांतहीन बना दिया। अधिकांश मंडलवादी दल परिवार, जाति की राजनीति के साथ भ्रष्ट आचरण के दोषी बनते गए। इसके परिणाम भी सामने हैं।

राजनीति और धर्म के प्रति लोहिया के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। यदि कम्युनिस्टों और समाजवादियों द्वारा इन विचारों का अनुसरण किया जाता तो आज उनकी स्थिति अलग होती। राज्य विशेष में राजनीतिक सफलता मिल जाने के बावजूद वामपंथी एवं समाजवादी आस्तिक-नास्तिक के कठघरे से बाहर नहीं निकल पाए और यही एक बड़ा कारण रहा कि देश के सभी हिस्सों में उनकी स्वीकार्यता नहीं बन पाई। आज श्रीराम से जुड़े आयोजन मात्र से इन दलों पर पाला बदलने, तुष्टीकरण के प्रयास आदि के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि धर्म का राजनीतिक और राजनीति का धार्मिक इस्तेमाल हुआ है। आज की दुनिया भिन्न और बदली हुई है। सोवियत संघ के विघटन के बाद समूचे पूर्वी यूरोप का सांस्कृतिक एवं धार्मिक हुलिया बदल गया।

भारतीय समाज में धर्म और उससे जुड़े प्रतीकों की जड़ें गहरी भी हैं और पुरानी भी। हमारे यहां धार्मिक प्रचारकों और गुरुओं की लंबी फेहरिस्त है, लेकिन समाज सुधारकों के नाम पर चंद महानुभाव ही हैं जो अपनी विश्वसनीयता रखते हैं। मौजूदा परिप्रेक्ष्य में वामपंथियों ने अगर इस मर्ज को समझा है तो यह स्वागतयोग्य है, लेकिन उन्हें भी ढोंग एवं आडंबर के प्रपंच से बचकर 'रामायण महीने' का आयोजन करना होगा, क्योंकि धर्म और राजनीति के अविवेकी मिलन से दोनों भ्रष्ट होते हैं। किसी एक धर्म को किसी एक राजनीति से नहीं मिलना चाहिए। इससे सांप्रदायिक कट्टरता जन्म लेती है। धर्म और राजनीति को अलग रखने का मतलब यही है कि सांप्रदायिक कट्टरता से बचें और दोनों का घालमेल न करें। सिद्धांत आधारित धार्मिक कार्यक्रम एवं राजनीति जनकल्याण के हित में भी होंगे। इससे धर्म भी तार्किक होंगे और मार्क्सवादी भी व्यावहारिक होंगे।

(लेखक जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

प्रभु स्मरण

मनुष्य हर चीज को समय से पूर्व पाने के लिए आतुर रहता है। किंतु कर्म के वृक्ष पर भाग्य के फल को तभी पकना है जब लीलाधारी प्रभु ने उसे पकने के लिए निर्दिष्ट किया है। दिसंबर में पकने वाला फल, वसंत ऋतु में खिलने वाला सुरभित फूल न फरवरी में पक सकता है, न पतझड़ में ही खिल सकता है। यदि मनुष्य अपनी कृत्रिम बुद्धि एवं ज्ञान से इस अवधि में कुछ अंतर लाता भी है तो उसकी नैसर्गिकता एवं मौलिकता अवश्य प्रश्नचिह्नित होती है। कर्म करना मनुष्य के हाथ में है, फल देना ईश्वर के हाथ। हम सब सांसारिक संबंधियों रूपी मजदूरों के ठेकेदार मात्र हैं जो इस लोक में उद्देश्यों के किसी खास कलात्मक एवं स्मरणीय भवन को बनाने के लिए लीलाधारी द्वारा किसी विशेष कालखंड के लिए प्रतिनियुक्त हैं। हम अपने तथाकथित मजदूरों के समूह को सुविधाएं जुटाकर सुखी रखने का उपक्रम कर सकते हैं, लेकिन उनके संचित कर्मों के फल से उन्हें वंचित नहीं कर सकते।

उनके भाग्यफल एवं कर्म की डोर तो केवल ईश्वर के हाथ में है। जीवन के रंगमंच में मनुष्य की भूमिका महज दर्शक भर की है। वह उस नाटक से प्रसन्न अथवा क्षुब्ध भर हो सकता है, लेकिन कर कुछ नहीं सकता। व्यक्ति निष्क्रिय हो दूसरों के भविष्य की चिंता में अपने वर्तमान को रुग्ण करता रहता है जो पुनः उसके संताप का कारण बनता है। मनुष्य के कर्म के चक्र को चलायमान रखने के उद्देश्य से ईश्वर ने भविष्य एवं उसके कर्मफल को उससे वंचित रखा है। यदि किसी को अपने भविष्य का सुखद परिणाम पूर्व में ही ज्ञात हो जाए तो वह उस दिशा की ओर लगने वाले प्रयासों की गति धूमिल ही नहीं, अत्यंत धीमी भी कर देगा। जीव सक्रिय एवं सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर होता रहे, इसलिए लोकल्याणकारी ईश्वर ने यह भविष्य-दर्शन फल जीव को बताने से परहेज भी किया है, ताकि वह निरंतर आस्थावान एवं आशावान रहकर सार्थक दिशा में उद्योग करता रहे। सांसारिक विषय-वासनाओं की चिंता छोड़ मनुष्य यदि ईश्वर की साधना, भक्ति की त्रिवेणी में चिंतारहित हो पवित्र मन से डुबकी लगाए तो उसका बीड़ा ईश्वर अपने हाथ ले उसे सांसारिक भवसागर से पार लगाने का स्वतः उपक्रम कर लेंगे। वह साफ मन से आस्था एवं विश्वास के साथ प्रभु का स्मरण करके तो देखे।

डॉ. दिनेश चमोला 'शैलेश'

देश में गहराता जल संकट

सुधीर कुमार

जल संरक्षण जरूरी है, ताकि पेयजल किल्लत, सूखा और अकाल जैसी आपदाओं से मानवता की रक्षा हो सके

नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में देश में गहराते पेयजल संकट और सूखते जलस्रोतों को देखते हुए 2024 तक पाइपलाइन के जरिए हरेक घर तक जल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नव सृजित जल शक्ति मंत्रालय के लिए 28,261 करोड़ और पेयजल स्वच्छता विभाग के लिए 20,016 करोड़ रुपये आवंटन की घोषणा की है। अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने सभी देशवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के वादे के साथ-साथ वर्षा जल संचयन, भूमि जल संभरण और अवशिष्ट जल का कृषि के लिए फिर से प्रयोग के लिए स्थानीय अवसंरचना के निर्माण पर बल देने की रूपरेखा भी तैयार की है।

नीति आयोग की मानें तो अभी जैसे हालात हैं उसके मुताबिक 2020 तक 21 शहरों में भूजल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। नीति आयोग की समग्र जल प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक देश में पानी की मांग उपलब्ध जल वितरण की दोगुनी हो जाएगी। आयोग ने चेतावनी भी दी है कि तब केवल पानी की समस्या की वजह से देश की जीडीपी में छह प्रतिशत की कमी आ सकती है!

बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से जल संरक्षण आंदोलन चलाने का आग्रह किया था। जिस रफ्तार से देश में जल स्रोत सूख रहे हैं, उससे जल संकट और भी भयावह होता जा रहा है। भारत सरकार ने जल से संबंधित सभी विषयों पर त्वरित निर्णय लेने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के नाम से एक नया मंत्रालय बनाया है। गत 1 जुलाई को सरकार ने देश के 256 जिलों में 'जल शक्ति अभियान' शुरू किया है। इसके तहत जल संरक्षण एवं वर्षा जल के संचय पर जोर दिया जा रहा है। तमिलनाडु देश का पहला राज्य है, जहां वर्षाजल संचयन को अनिवार्य बनाया गया है, जबकि राजस्थान में आज भी परंपरागत तरीके से तालाब, जोहड़ एवं सरोवर बनाकर जल संग्रहण किया जाता है, लेकिन अन्य राज्य वर्षा जल संरक्षण एवं संग्रहण के प्रति उदासीन क्यों हैं?

फिलहाल वर्षा जल संग्रहण के लिए चार बातों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जैसे- जलस्रोतों की सफाई, अधिक से अधिक तालाब का निर्माण, पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार और वर्षा जल संरक्षण पर जोर। वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा के जल को रोकने और एकत्र करने की विधि है। इसके माध्यम से वर्षा जल की प्रत्येक बूंद को संरक्षित करने के लिए नलकूपों, गड्ढों एवं कुओं में एकत्रित किया जाता है। यह न सिर्फ भूमिगत जल के स्तर को नीचा होने से रोकता है, बल्कि मृदा अपरदन को रोकने तथा जल में उपस्थित फ्लोराइड और नाइट्रेट जैसे प्रदूषकों को कम करने के साथ ही जल के अन्य स्रोतों पर हमारी निर्भरता भी कम करता है। बहरहाल दुनिया को जल संकट से उबारने के लिए जल संरक्षण के आसान तरीकों को अपनाना जरूरी है, ताकि पेयजल किल्लत, सूखा और अकाल जैसी आपदाओं से मानवता की रक्षा हो सके।

(लेखक बीएचयू में अध्येता हैं)

मेलबाक्स

भ्रष्टाचार सबसे बड़ी बाधा

बजट के लक्ष्य पाने की चुनौती शीर्षक से लिखे अपने लेख में संजय गुप्त ने हाल ही में पेश हुए आम बजट का विश्लेषण करते हुए देश की कर प्रणाली की कमियों को उजागर किया है। साथ ही सरकार को कर इकट्ठा करने में पेश आने वाली चुनौतियों को दूर करने के संबंध में कुछ सुझाव दिया है। सवाल है कि जिस देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका हो, जहां हर कोई अपने स्वार्थ को सर्वोपरि मान रहा हो, वहां कर प्रणाली सुचारू रूप से कैसे चलेगी? मोदी सरकार ने अपनी पहली पारी में देश की कर व्यवस्था में सुधार लाने और कालेधन पर नकेल कसने के लिए नोटबंदी और जीएसटी जैसे ऐतिहासिक फैसले भी लिए थे, लेकिन अफसोस ये फैसले भी देश की कर प्रणाली और भ्रष्टाचार की बीमारी को दूर नहीं कर पाए। उल्टे कुछ लोगों के कारोबार और रोजगार पर भारी पड़ गए। उद्योग-धंधे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, क्योंकि ये देश के खजाने को तो भरते ही हैं, रोजगार भी उपलब्ध कराते हैं। ऐसे में सरकार को देश की कर व्यवस्था को इतना सरल बना देना चाहिए कि कारोबारी आसानी से अपना कर सरकारी खजाने में जमा करा सकें। इसके साथ ही सरकारों को इनके व्यापार की राह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के प्रयास भी प्राथमिक आधार पर करने चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

बूंद-बूंद पानी का संचय

चेन्नई में सूखे के हालत ने हमें चेतने का एक अवसर दिया है कि कैसे हमें एक-एक बूंद पानी का संचय करना जरूरी है। नहीं तो जल संकट आज केवल देश के दक्षिण में है कल उत्तर में भी हो सकता है। अगर आने वाले दिनों में चेन्नई जैसे हालातों का सामना देश के अन्य राज्यों को भी करना पड़े तो देश का विकास अवरुद्ध होगा, साथ ही जान बजाने के भी लाले पड़ जाएंगे। वैसे भी इस साल भीषण जल संकट से जूझ रहे दुनिया के 400 शहरों की श्रेणी में चेन्नई पहले स्थान पर है। 30 सालों में सबसे भीषण सूखे की चपेट में आया चेन्नई देश की आवाम को जल संचय के प्रति सचेत कर रहा है। जल का अनावश्यक दोहन न करना और वर्षा के जल का संचय करना इसका एक मात्र विकल्प है। जिसके लिए हमें जल के दोहरे इस्तेमाल की ओर कदम बढ़ाने होंगे। इस तरह से हम एक तीर से दो निशाने साध सकते हैं। जिस तरह से चेन्नई की प्रमुख झीलें सूखने से वहां जल संकट उत्पन्न हुआ हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि हमारे आसपास की नदियां, तालाब और नल कभी सूखने न पाएं। जल संचय के प्रति सरकारें हमेशा से प्रयासरत हैं। हाल ही में जल